वार, तहसीलवार तथा सर्किलवार कितने कितने लेखपालों को भुगतान किया गया और कितने लेखपालों को अभी तक इस राशि का भुगतान नहीं किया गया; और

(ख) जिन लेखपालों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उनको कब तक भुगतान किये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) और (ख) जानकारी संग्रहीत की जा रही है ।

Immoral Traffic in Women in Delhi

5124. DR. SUSHILA NAYAR : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that immoral traffic in women is carried on in Sarai-Rohilla Loco Shed Quarters close to the Shidipura Police Station, Delhi;

(b) whether it is also a fact that it is being carried on with the help of some police officials of Shidipura Delhi;

(c) if so, whether any inquiry has been conducted into this matter; and

(d) the details thereof and the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI) PHULRENU GUHA : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Promotion of Commercial Crops Under Fourth Plan

5125. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a number of package programmes are envisaged under a scheme drawn up for promoting commercial crops under the Fourth Five Year Plan with a view to boosting their production and export for implementation by the Cooperative Societies, industrialists, and Chambers of Commerce in their respective areas of work; and

(b) if so, the salient features of these package programmes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) Yes, Centrally Sponsored Schemes for raising the production of Cotton, Groundnut Jute, Tobacco, Lac, Pepper, Cashewnut and Coconut so as to make larger quantities available for export/import substitution, have been proposed for implementation in the maximum potential areas in different States.

(b) The details of the programmes are being worked out.

कृषि, उत्पाद बिक्री समिति, बुलन्दशहर

5126. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश उत्पाद बिक्री समिति अधिनियम, 1964 में कृषि उत्पाद बिक्री समितियों में कच्चे आढ़तियों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बुलन्दशहर कृषि उत्पाद बिक्री समिति में कच्चे आढ़तियों को आवश्यक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कच्चा आढ़ती संघ ने उस व्यक्ति को हटाने की मांग की है ? जिसे उनका प्रतिनिधि नामजद किया गया है और दो अन्य प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कच्चा आढ़ती संघ, बुलन्दशहर के सचिव ने अपने 30 नवम्बर, 1968 के पत्र में कमीशन एजेन्टों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को 'हटाने' के लिए नहीं, उसका त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया है। अन्य दो प्रतिनिधियों की नामजदगी के लिए कच्चा आढ़ती संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी, कच्चा आढ़ती संघ ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य उपयुक्त की नामजदगी के लिए प्रार्थना की है ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस मामले में आवश्यक पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा मकई की बिक्री

5127. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलन्दशहर जिले में किसानों द्वारा खुले बाजार में मकई की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार स्वयं भी उनसे मकई नहीं खरीद रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किसानों द्वारा खुले बाजार में मकई बेचने पर पाबन्दी लगाने के क्या कारण हैं जब सरकार स्वयं भी उनसे नहीं खरीद रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम दोनों ने बुलन्दशहर सहित उत्तर प्रदेश की मंडियों में मकई की खरीदारी की । भारतीय खाद्य निगम खरीदारी कर रही है जबकि राज्य सरकार ने हाल ही में मंडियों में खरीदारी बन्द कर दी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cotton Development Council, Bombay.

5128. SHRI S. S. KOTHARI :
SHRI LOBO PRABHU :

Will the Minister of FOOD & AGRICULTURE be pleased to state :

(a) when the Cotton Development Council in Bombay came into being, the expenditure incurred on it and its achievements so far;

(b) what are the new varieties of cotton that have been developed on a commercial scale, since the abolition of the Indian Central Cotton Committee and in what parts of India they are being grown;

(c) what has been the expenditure incurred on research and development of cotton during each of the last five years; and

(d) whether Government have any specific plans for increasing raw cotton production in the coming years in order to minimise the country's dependence on foreign cotton and, if so, what are they ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNA SAHIB SHINDE) : (a) The Cotton Development Council came into being from the 19th May, 1966. The expenditure incurred on it so far comes to Rs. 19,953/--. The council is an advisory body and has made several useful suggestions concerning the developmental programmes on cotton including price policy.

(b) While on new varieties have been developed on a Commercial scale since the